भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-283

दिनांक 02 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

हरियाणा में राष्ट्रीय पशुधन मिशन

283.श्री सतपाल ब्रह्मचारीः

श्री जय प्रकाशः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हरियाणा के सोनीपत और हिसार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) के अंतर्गत लाभान्वित पशुपालकों की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या कई गांवों में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, पशु स्वास्थ्य शिविर और प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से नहीं चलाए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अधिकांश योजनाएं केवल कागजों तक ही सीमित हैं और पशुपालकों को कोई वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त क्षेत्र में दूध उत्पादन, नस्ल सुधार तथा चारे की उपलब्धता में हुई प्रगति का कोई मूल्यांकन कराया है;

(ङ) क्या उक्त लाभार्थियों को राजसहायता और सहायता राशि समय पर नहीं मिल रही है, जिसके कारण योजना का प्रभाव सीमित है;

(च) क्या कुछ क्षेत्रों में निधि का समय पर उपयोग नहीं किया गया था, जिसके कारण योजनाएं अधूरी रह गईं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार ने उक्त मिशन की निगरानी प्रणाली को मजबूत करने और ग्रामीण पशुपालकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) पशुधन बीमा घटक के अंतर्गत पशुधन बीमा योजना के कार्यान्वयन हेतु हरियाणा सरकार को उसकी मांग के अनुसार सहायता प्रदान की गई। हरियाणा सरकार के पशुपालन विभाग ने सूचित किया है कि पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत लाभान्वित किसानों की संख्या निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिनांक 27-11-2025 तक)			
क्र. सं.	**जिले का नाम**	**कुल लाभान्वित लाभार्थी**	**कुल बीमित पशु**
1	**हिसार**	29112	68790
2	**सोनीपत**	9121	21584
कुल		**38233**	**90374**

इसके अलावा, राष्ट्रीय पशुधन मिशन- उद्यमिता विकास कार्यक्रम (NLM-EDP) के अंतर्गत, हिसार जिले में एक परियोजना को अनुमोदन दिया गया है।

(ख) और (ग) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को अनुपूरित और संपूरित करने के लिए, भारत सरकार दिसंबर 2014 से हरियाणा सहित पूरे देश में देशी नस्लों के विकास और संरक्षण, बोवाइन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन और दुग्ध उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) कार्यान्वित कर रही है। इस योजना का लाभ हरियाणा सहित देश के सभी डेयरी किसानों को मिल रहा है।

हरियाणा में, कुल 9,18,621 कृत्रिम गर्भाधान (AI) किए गए हैं, 6,27,406 पशुओं का गर्भाधान किया गया है और 4,54,025 किसान लाभान्वित हुए हैं।

पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) के पशु रोग नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (ASCAD) घटक के अंतर्गत, राज्य की मांग, कार्य योजनाओं और दिशानिर्देशों के आधार पर, अच्छी पशुपालन प्रथाओं और पशु चिकित्सा देखभाल संबंधी जागरूकता, प्रशिक्षण और प्रचार-प्रसार हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस घटक के अंतर्गत, हरियाणा को 156.26 लाख रुपये संस्वीकृत किए गए हैं।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) के अंतर्गत, हरियाणा में पशुधन बीमा और एनएलएम-ईडीपी योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, एलएचडीसीपी योजना के अंतर्गत, हरियाणा सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खुरपका-मुँहपका रोग (FMD) और ब्रुसेलोसिस के टीकाकरण के लिए 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

हरियाणा में, कुल 264.48 लाख एफएमडी टीके लगाए गए हैं, जिससे 16,63,514 किसान लाभान्वित हुए हैं, और 6.08 लाख ब्रुसेलोसिस टीके लगाए गए हैं, जिससे 3,64,510 किसान लाभान्वित हुए हैं। पेस्ट डेस पेटिट्स रुमिनेंट्स (PPR) के लिए भी टीकाकरण किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा में 2,009 टीके लगाए जा चुके हैं, और क्लासिकल स्वाइन ज्वर (CSF) के लिए भी टीकाकरण किया जा रहा है, जिसमें 371 टीके लगाए गए हैं, जिससे क्रमशः 92 और 31 किसान लाभान्वित हुए हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को टीकाकरण संबंधी सहायक सामग्री की खरीद, कोल्ड चेन अवसंरचना को सुदृढ़ करने, टीका लगाने वालों के पारिश्रमिक, जागरूकता पैदा करने और संबंधित कार्यकलापों के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, हरियाणा में 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ कार्यरत हैं, जो किसानों के द्वार पर पशु स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करती हैं।

(घ) नीति आयोग ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन का मूल्यांकन अध्ययन किया है। इस अध्ययन के अतिरिक्त, आईसीएआर (ICAR)-भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झाँसी ने अपने तकनीकी बुलेटिन "चारा परिदृश्य: राज्यवार स्थिति का पुनर्परिभाषण" (2019) में बताया है कि हरियाणा में क्रमशः 94.60 प्रतिशत और 10.50 प्रतिशत अतिरिक्त हरा और सूखा चारा उपलब्ध है।

इसके अलावा, केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हस्तक्षेपों के कारण, हरियाणा में दूध उत्पादन वर्ष 2017-18 में 9809.00 हजार टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 12220.20 हजार टन हो गया है, जो 24.58 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है (मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी, 2024)

(ङ) और (च) एनएलएम-ईडीपी (NLM-EDP) के अंतर्गत, आवेदकों द्वारा समर्पित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा रहे हैं। राज्य कार्यान्वयन एजेंसी से अनुशंसा और परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदन के बाद, परियोजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति के आधार पर लाभार्थियों को सब्सिडी जारी की जाती है। सब्सिडी की पहली किस्त तब जारी की जाती है जब लाभार्थी परियोजना की लागत का 25% अवसंरचना पर खर्च कर चुका होता है। शेष सब्सिडी राशि लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत परियोजना पूर्णता रिपोर्ट और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उसका सत्यापन करने के बाद जारी की जाती है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 21 अनुमोदित मामलों में से 6 लाभार्थियों को पहले ही 1.09 करोड़ रुपये की सब्सिडी की पहली किस्त मिल चुकी है, तथा एक लाभार्थी को 0.184 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त भी मिल चुकी है।

(छ) इस विभाग की योजनाओं की निगरानी हेतु, सभी कार्यक्रमों और योजनाओं की देखरेख हेतु राष्ट्रीय स्तर के मॉनिटर नियुक्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) के अंतर्गत पशुपालकों में जागरूकता बढ़ाने हेतु राज्य सरकारों को प्रशिक्षण और कार्यशाला आयोजित करने में सहायता प्रदान की जा रही है।

*****